

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक, 1941 (श॰)

संख्या- 897 राँची, सोमवार,

11 नवम्बर, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

31 अक्टूबर, 2019

विषय:- राज्य योजना से वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित 107.033 करोड़ रु॰ की लागत पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त दुमका जलापूर्त्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-05/जलापूर्ति/दुमका/20/2019/न॰वि॰आ॰-5384-- भारतीय संविधान के 74 वें संविधान संशोधन के आलोक में राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य के नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में दुमका शहरी जलापूर्ति परियोजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

2. प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत मसानजोर जलाशय में एक इंटेक वेल, आसनसोल कुर्वा गाँव में 7 MLD का एक WTP, समुचित वितरण व्यवस्था, हरवाडीह एवं श्रीआमरा में दो GDR, लीची बगान एवं गिधनी पहाड़ी में दो GSR, और हरवाडीह एवं खंडेलवाल टेक्नोपार्क में दो सम्प का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, तािक प्रस्तावित क्षेत्र में न सिर्फ शत प्रतिशत Network coverage हो बल्कि Water pressure की समस्या का समुचित समाधान भी संभव हो सके।

- 3. प्रस्तावित परियोजना में दुमका शहरी क्षेत्र में पूर्व से चल रही जलापूर्ति योजना का आवर्धन एवं सुद्दिकरण (Augmentation & Strengthening) शामिल है, जिसमें पूर्व से ही दुमका नगर परिषद् एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों के 31 गाँवों को जलापूर्ति की जा रही थी। उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में संपन्न Stakeholder's Meeting की कार्यवाही के आलोक में पुनः जल शोध संस्थान से नगर परिषद् तक पाइपलाइन बिछाने के क्रम में मार्ग में पड़ने वाले 21 अन्य गावों को भी सम्मिलित करते हुए जलापूर्ति योजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की गई है। इस प्रकार प्रस्तावित परियोजना में दुमका नगर परिषद् एवं आस-पास के कुल 52 गावों में लगभग 21355 घरों में जल संयोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित की गई है।
- 4. प्रस्तावित परियोजना में अपर्याप्त वितरण व्यवस्था (Distribution Network) के कारण उत्पन्न किठनाईयों के निराकरण एवं भविष्य के मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2052 तक जनसंख्या के मांग को ध्यान में रखते हुए योजना का Network Design तैयार किया गया है।
- 5. इस परियोजना के सुत्रण में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी Service Level Benchmarks को ध्यान में रखा गया है एवं भविष्य के मांग के आधार पर 24X7 जलापूर्ति व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा।
- 6. इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत किए गए Model Bid Document का उपयोग किया जाएगा।
- 7. उक्त परियोजना का कार्यान्वयन जुडको लि॰ द्वारा खुली एवं प्रतिस्पर्द्धी निविदा पद्धति (National Competitive Bidding) के माध्यम से सुयोग्य एजेन्सी का चयन कर ससमय सुनिश्चित किया जाएगा।
- 8. परामर्शी Feedback Infra Pvt. Ltd. द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निम्नवत् तकनीकी अनुमोदन प्रदान की गई है :-

COST ESTIMATE FOR DUMKA WATER SUPPLY SCHEME			
Sl. No.	Description of Work	Total Amount in INR.	
1	Pipe Network		
a	Gravity Main	19905047.00	
b	Pumping Main	18972060.00	
С	Distribution Network	403463684.00	
2	ESR's		
а	At Lichi Bagan – 1900 KL, 20 Mtr. Staging Height	13542250.00	
b	At Gidhni Pahari – 1050 KL, 20 Mtr. Staging Height	8525703.00	
3	GSR's		
а	At Harwadih – 1550 KL	7308170.00	
b	At Shri Amra Hillock – 400 KL	3411107.00	
4	Sump's		
a)	Intermediate Sump of 1,500,000 Lit	5927987.00	
b)	Proposed Sump at Harwadih - 1,00,000 Lit	4184825.00	
5	WTP - 7 MLD	20539284.00	
6	Approch bridge cum Gangway	45543306.00	
7	Intake Well	30255034.00	
8	Pumping Machinery & allied works	15959170.00	
9	Electrical Cost	24437995.00	
10	SCADA & Automation work	13624705.00	
	Total	635600327.00	

	Ţ.	
	Total Civil Cost Including GST @ 12%	76272039.00
Α	Total with GST	711872366.00
	Add Labour Cess @ 1%	7118724.00
	Total	718991090.00
	Crossings & Utility Shifting	2000000.00
В	Design and Supervision Consultancy charges	
	DPR Consultancy Charges @ 0.76% on (A)	5410230.00
	PMC Charges @ 1.86% on (A)	13240827.00
	Total-(B1)	757642147.00
С	JUIDCO Charges on A	
	JUIDCO Charges on 1st Rs. 10 Crore @ 7%	7000000.00
	JUIDCO Charges above Rs. 10 Crore upto 100 Crore @ 5%	30593618.00
	Total JUIDCO Charges	37593618.00
D	Miscellaneous work charges	12000000.00
	Total CAPEX	807235765.00
E	Operation and Maintainers charges for 5 years (OPEX)	263100062.00
	Total (B1+C+D+E)	1070335827.00
	Or Say	1070336000.00

उक्त परियोजना हेतु निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

- 9. उपरोक्त तालिका के अनुसार उक्त परियोजना के कार्यान्वयन की लागत राशि (CAPEX) 8072.35765 लाख रु॰ है और 5 वर्षों तक के परिचालन एवं रख-रखाव (O&M) में व्यय होने वाली राशि (OPEX) 2631.00 लाख रु॰ है।
- 10. उक्त परियोजना का वित्त पोषण वर्तमान एवं उत्तरोत्तर वर्षों में राज्य योजना मद के सुसंगत बजट शीर्ष से किया जाएगा।
- 11. उपरोक्त परियोजना के निर्धारित अवयवों के निर्माण हेतु चिन्हित सभी भूखंड जो झारखण्ड सरकार की हैं, के निःशुल्क हस्तांतरण के लिए संबंधित विभागों को अधियाचना भेजी जा चुकी है।
- 12. चयनित संवेदक द्वारा उद्धृत राशि के स्वीकृत प्राक्कित राशि से अनुज्ञेय सीमा तक अधिक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत् कार्य आवंटित किया जाएगा।
- 13. परियोजना के रख-रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय-सीमा के लिए एकरारनामा में कार्य योजना (O&M Plan) का प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-
 - क) रख-रखाव हेतु चयन किए जाने वाली संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।
 - ख) गुणवत्तायुक्त जलापूर्ति एवं निर्बाध सेवा के अनुरूप मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, इन मापदण्डों के आधार पर ही चयनित संवेदक को भ्गतान किया जायेगा।
 - ग) रख-रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रिडींग कर निकाय के द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Charges) के अनुसार नवीनतम तकनीकों (E-Mail, SMS आदि) का प्रयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया

जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा इस विपत्र के विरुद्ध भुगतान किया जा सकेगा।

- घ) संवेदक को रख-रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- 14. उक्त परियोजना का कार्यान्वयन 24 माह में पूर्ण करना निर्धारित है।
- 15. राज्य योजना से वित्त पोषण हेतु उक्त 107.033 करोड़ रु॰ की लागत पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त दुमका जलापूर्त्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 16. दिनांक-25.10.2019 को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद् बैठक में मद संख्या-26 के रूप में उक्त योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह, सरकार के सचिव।
